भारतीय रिज़र्व बैंक

बनाम

सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड एवं अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 4193)

9 जून, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी.पी. नाओलेकर, जे.जे.]

वित्तीय निगम - गंभीर कमज़ोरियों का आरोप - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया -आरबीआई द्वारा पारित जवाबी आदेश पर विचार करने के बाद निगम को मौजूदा और नए जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया - उच्च न्यायालय ने निगम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की - माना: यद्यपि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है, फिर भी, कार्यवाही की प्रकृति और तत्काल मामले में शामिल विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, आरबीआई के लिए यह उचित होगा कि वह सुनवाई का अवसर दे। निगम - तदनुसार आदेश दिया गया - आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा - जब तक मामले का नए सिरे से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक आरबीआई द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.6.2008 को प्रभावी नहीं किया जाएगा -उसी समय उच्च न्यायालय द्वारा निगम को दिया गया अंतरिम संरक्षण प्रभावी नहीं होगा - पूरे मामले का निपटारा - प्रशासनिक कानून - कृतिक न्याय के सिद्धांत - अवसर सुनवाई का - अंतरिम आदेश.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4193/2008।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के सीडब्ल्यूपी 2008 की संख्या 5059 (एमबी) में अंतरिम आदेश दिनांक 5.6.2008 से उत्पन्न।

टी.आर. अंध्यारुजिना, रमेश बाबू एम.आर., मनीषा, सृंजॉय बनर्जी और स्वाति सेतिया अपीलकर्ता के लिए।

मुकुल रोहतगी, प्रशांत चंद्रा, रंजीत कुमार, उदय यू. ललित, के.के. लाहिड़ी, सतीश किशनचानी, गौरव केजरीवाल और एम. केशव मोहन प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय व आदेश डॉ. अरिजीत पसायत, जे. सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना।

इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है प्रतिवादी नंबर 1 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना।

2. संक्षेप में बताया गया तथ्यात्मक परिदृश्य इस प्रकार है:

अपीलकर्ता द्वारा 09.05.2008 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को यह बताने की आवश्यकता थी कि प्रस्तावित कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, एक विस्तृत उत्तर 02.06.2008 को दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने यह रुख अपनाया कि कारण बताओ उत्तर प्रस्तुत करने से पहले 20.5.2008 को चर्चा की गई थी। अंतिम आदेश दिनांक 04.06.2008 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-कंपनी को मौजूदा जमाकर्ताओं और नए जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

ये अन्य दिशाओं के अतिरिक्त मुख्य दिशाएँ थीं। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, यह कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता को वर्तमान अपीलकर्ता के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिला और इसलिए, इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी, एजेंट, कर्मचारी और जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं। उच्च न्यायालय ने 05.06.2008 को आक्षेपित आदेश पारित किया और उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक उसके समक्ष आक्षेपित दिनांक 4.6.2008 के आदेश के संचालन और प्रवर्तन पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 की कुछ गतिविधियों पर आपत्ति जताई गई थी, इसलिए उन्हें सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने और समय-समय पर वर्तमान अपीलकर्ता के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता को किसी भी नई जमा राशि को स्वीकार करने से रोका गया था जिसकी परिपक्वता जून, 2010 से अधिक होगी। मामले को जुलाई, 2008 के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टी.आर. अंध्यारुजिना ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को अपना मामला रखने का कोई अवसर दिए बिना, रिट याचिका को वस्तुतः अनुमति देकर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जैसा कि अंतरिम आदेश द्वारा संक्षेप में अंतिम राहत मांगी गई थी। रिट याचिका मंजूर कर ली गई। यह उनका रुख था कि रिट याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए गए थे और रिट याचिकाकर्ता द्वारा की गई विभिन्न कमजोरियों को कारण बताओ नोटिस और उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आदेश में उजागर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई की आवश्यकता थी। कारण बताओ नोटिस दिनांक 09/05/2008 और आदेश दिनांक 04/06/2008 के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि कई अवैधताएं की गई हैं और प्रतिवादी नंबर 1 के कामकाज में

पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है। कारण बताओ नोटिस और आदेश दिनांक 04.06.2008 में कई गंभीर कमजोरियों को विस्तार से निपटाया गया है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को अपना मामला अपीलकर्ता के समक्ष उस आदेश से पहले रखने का अवसर दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने से पहले, दायर करने के बाद लागू किया गया था। 02.06.2008 को कारण बताओ उत्तर में वह यह दर्शाने की स्थिति में होता कि नहीं जैसा कि कारण बताओ में विचार किया गया था, कार्रवाई की जानी आवश्यक थी और/या अनुमति दी जानी थी।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इसमें शामिल विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह उचित होगा कि वह प्रतिवादी नंबर 1 को सुनवाई का अवसर दे ताकि यदि सलाह दी जाए तो वह कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अपनाए गए पक्ष को पुष्ट करने के लिए सामग्री रख सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना सही है कि वर्तमान मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। लेकिन कार्यवाही की प्रकृति के कारण सुनवाई का अवसर उचित होगा। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि हमने ऐसा सभी मामलों में लागू होने के लिए कहा है। मामले की विशिष्ट प्रकृति के कारण, हम ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के 12.06.2008 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा जब मामले की सुनवाई होगी। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए यह खुला है कि वह ऐसी सामग्री रखे जिस पर वह दृढ़ता से विचार करे। कहने की जरूरत नहीं है कि प्राधिकरण मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करेगा और एक नया आदेश पारित करेगा। जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

मामले का नये सिरे से निपटारा नहीं किया जाता, दिनांक 04.06.2008 का आदेश प्रभावी नहीं होगा। साथ ही, प्रतिवादी नंबर 1 को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा भी प्रभावी नहीं होगी। चूँकि पूरे मामले का निपटारा इस अपील में किया जा रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।'

6. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

आर.पी.

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी अजय कुमार शर्मा-III (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।